दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 02 दिसंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-04, अंक- 65

महत्वपूर्ण एवं खास

पिता ने बच्चों संग किया आत्मदाह

गोरखपुर(आरएनएस) ।पिता ने अपने दो बच्चों के साथ किया आत्मदाह, मौके पर ही तीनों की हुई मौत। गीडा थाना क्षेत्र के सरया गांव में बुधवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है। सरया निवासी 36 वर्षीय मदन कन्नौजिया अपनी 7 वर्षीय पुत्री अन्नपूर्णा व 5 वर्षीय बेटे शेषनाथ के साथ घर का दरवाजा अन्दर से बंद करके एलपीजी गैस सिलेंडर की पाइप निकाल कर आग लगा लिया। जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई।

आ रहा साउदी अरब का साइक्लोन जवाद, भारी बारिश का खतरा

रांची (आरएनएस)। बंगाल की खड़ी में आने वाले चक्रवात का नाम जवाद है जिसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है। इस चक्रवात के काफी ताकतवर होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के साथ तेज हवा भी चल सकती है। कई दिनों तक इसका असर दिख सकता है।

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला आरक्षक को दी लिंग परिवर्तन कर पुरुष बनने की अनुमति

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने महिला पुलिस आरक्षक को लिंग परिवर्तन की अनुमति दी है। महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को लिंग परिवर्तन की अनुमति पुलिस महानिदेशक ने प्रदान की। महिला आरक्षक को बचपन से जेंडर आइडेंटटी डिसआर्डर की पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों द्वारा की गई। महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) द्वारा पुरुषों की भांति समस्त पुलिस कार्य जिले में किया जाता रहा है तथा उनके द्वारा विधिवत आवेदन, शपथ पत्र, और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में महिला से जेंडर परिवर्तन की मंशा की अधिसूचना प्रकाशित कराने उपरांत आवेदन पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया। पुलिस मुख्यालय द्वारा गृह विभाग से अनुमति हेतु मार्गदर्शन चाहा गया। किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के तारतम्य मे विधि विभाग से विधिक परामर्श के उपरांत गृह विभाग द्वारा अमिता (परिवर्तित नाम) को जेंडर बदलने की अनुमति के आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदान किए गए। मध्य प्रदेश गृह विभाग के सामने यह पहला मामला था, जिसमें महिला कांस्टेबल को लिंग परिवर्तन करवाने की अनुमति दी गई है।

भोपाल में नकली सैनिटाइजर फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, कई जगह सप्लाई करने की थी तैयारी

भोपाल (आरएनएस)। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते आपदा में अवसर की तलाश करते बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली सैनिटाइजर बनाने वाले गिरोह फिर सक्रिय हो गए हैं। राजधानी की पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर दबिश देते हुए सैकड़ों लीटर नकली सैनिटाइजर जब्त कर लिया है। फैक्ट्री के संचालक पर एफआइआर दर्ज की गई है। रातीबड थाना प्रभारी सुदेश तिवारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके स्वच्छ हर्बल कंपनी कलखेड़ा रोड द्वारा बड़े पैमाने पर नकली सैनिटाइजर बनाया जा रहा है। इस सैनिटाइजर को कैन में पैक करते हुए नामी-गिरामी कंपनी के स्टीकर लगाकर बड़े दामों पर बेचकर अवैध लाभार्जन किया जा रहा है। सूचना पर उक्त ब्रांडेड कंपनी के अधिकारियों को साथ लेकर उक्त फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मौके से 156 नग पांच लीटर की कैन में 760 लीटर सैनिटाइजर जब?त किया गया। आरोपित फैक्ट्री संचालक अक्षय शर्मा निवासी जेके पार्क कोलार रोड एवं फाइज आलम निवासी पुल वोगदा के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वे लंबे समय से उक्त कार्य में लिप्त थे। बीच में व्यापार कम हो गया तो यह काम रोक दिया। हाल ही में कोरोना के नए वैरिएंट के बाद तीसरी लहर की आशंका के चलते नकली सैनिटाइजर बनाने का कार्य पुनः शुरू कर दिया था। इस काम में इनके द्वारा 200 से 250 रुपये के सैनिटाइजर को ब्रांडेड सैनिटाइजर के रूप में बनाने पर 2000 से 2500 रुपए का बेचकर 10 गुना तक लाभ अर्जित किया जाता था।

शीत सत्र में धरने पर बैठेंगे निलंबित सांसद

» राहुल ने भी किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली (आरएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत के मामले को उठाया। सत्र के शुरू होने के बाद हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सभापति को सत्र स्थगित करना पड़ा। लेकिन इस दिन संसद के अंदर ही सिर्फ हंगामा नहीं हुआ बल्कि संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रदर्शन किया। अपनी निलंबन वापसी की मांग को लेकर यह सभी राज्यसभा सासंद संसद परिसर में ही बने महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे धरना प्रदर्शन पर बैठ गए।

तृणमूल कांग्रेस की निलंबित राज्यसभा सांसद डोला सेन और शांता चेत्री के अलावा बुधवार को अन्य सभी निलंबित सांसद संसद परिसर में अपने निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों सांसद सत्र के दौरान हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक धरने पर बैठेंगी। यह धरना सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि इस धरना प्रदर्शन के दौरान अन्य निलंबित सांसद भी वहां पहुंचेंगे और अपना निलंबन वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगे। टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा, 'सांसदों का निलंबन उनके घमंड को दिखाता है जो बहुमत में है। जब वो विपक्ष में थें तब वो लोग भी संसद की कार्यवाही को बाधित करने का काम करते थे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।'

राहुल गांधी का निलंबित सांसदों को समर्थन- कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सांसदों को समर्थन देने पहुंचे। राहुल गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य कई नेता भी नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा, 'हम यह मांग करते हैं कि राज्यसभा के निलंबित सभी 12 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। हम एक बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे।'

शशि थरूर का सरकार पर निशाना- कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'केंद्र सरकार को समझना चाहिए की देश में दूसरे लोगों की आवाज को भी सुनना होगा। संसद विचार-विमर्श के लिए है। आपको लोगों को अपने विचार रखने की अनुमति देनी होगी। सिर्फ इस तरह से अब एक प्रजातांत्रिक संसद को चला सकते हैं।'

क्यों हुए सांसद निलंबित?- आपको याद दिला दें कि अगस्त के महीने में मॉनसून सत्र के दौरान इन 12 सांसदों को निलंबित किया गया था। इन सभी सांसदों पर राज्यसभा में भारी हंगामा मचाने और मार्शलों से हाथापाई करने का आरोप लगा था। उस सत्र में इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में झड़प हो गई थी। सांसदों ने कागज फाड़ दिए थे, धक्का-मुक्की की थी। बवाल इतना बढ़ गया था कि मार्शलों को भी बुलाना पड़ गया था। टीएमसी की महिला सांसद पर मार्शल से अभद्रता का आरोप भी लगा था। इसी हंगामे के बाद दोनों सदनों को समय से दो दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था।

वेंकैया नायडू ने कही है यह बात- राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा था कि 12 सांसदों का निलंबन वापस नहीं होगा। जिन सदस्यों ने संसद के अंदर हंगामा किया था उन्होंने इसके लिए अफसोस भी नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि विपक्ष द्वारा इन सांसदों की निलंबन वापसी की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता।

सरकार के पास नहीं है किसान आंदोलन में मृतकों का रिकार्ड : तोमर

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को संसद में बताया है कि सरकार के पास दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। विपक्ष की ओर से मृतक किसानों के परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चूंकि सरकार के पास किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे में आर्थिक सहायता देने का सवाल ही नहीं उठता।

किसान नेताओं का लंबे समय से यह दावा है कि सिंघु, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर लगातार कृषि कानूनों का विरोध करने वाले 700 से ज्यादा किसान अब तक जान गंवा चुके हैं। यह मौतें मुख्य रूप से मौसम की मार, गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों और आत्महत्या के कारण हुई हैं। इस बीच आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मांग की है कि सरकार बाकी लंबित मुद्दों पर किसान नेताओं के साथ बातचीत करे। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले बिल के पास होने के बावजबद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार एमएसपी पर कानूनी बनाने की उनकी मांग को स्वीकार नहीं करती है। किसानों ने यह भी मांग की है कि प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुए पुलिस केस भी वापस लिए जाएं और इस दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। किसानों ने दावा किया है कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उनसे पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

इस साल 115 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से किया पलायनः सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों पर हुए हमले और कश्मीरी पंडितों को फिर निशाना बनाने की घटनाओं के बीच 115 कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर छोड़ दिया। ये सभी कश्मीरी पंडित अपने-अपने परिवार के साथ जम्मू चले गए।

यह जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दिए गए एक लिखित जवाब में दी और बताया कि जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर जम्मू चले गए वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार ने बताया कि सर्दियों की शुरुआत में अक्सर सरकारी कर्मचारी कश्मीर से पलायन करके सरकारी कामकाजों, पढ़ाई व अन्य वजहों ने जम्मू में रहने लगते हैं।

आतंकी घटनाओं में कमी

जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशनों का असर काफी हद तक दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ व आतंकी घटनाओं में कमी आई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद से घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार 2018 में घुसपैठ की कुल 143 घटनाएं हुई थीं। जबकि साल नवंबर तक केवल 28 घुसपैठ की घटनाएं दर्ज की गई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2018 में 417 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि इस साल(21 नवंबर तक) 244 आतंकी घटनाएं हुई हैं।

आधुनिक भारत के निर्माण में महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ महत्वपूर्णः सीएम योगी

» मुख्यमंत्री ने विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ में डाली आहुति

अयोध्या (आरएनएस)। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने बुधवार को अयोध्या भ्रमण पर महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ द्वारा आयोजित परिक्रमा मार्ग पर आयोजित चल रहे राष्ट्र की संवृद्धि, शांति एवं विकास हेतु श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। यह यज्ञ विगत नवम्बर माह में शुरू किया गया था। जिसका समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पूर्णाहुति के साथ किया गया। इसके मुख्य आयोजक महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ एवं महर्षि रामायण सेवा न्यास के मुख्य ट्रस्टी अजय प्रकाश श्रीवास्तव आदि द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में शांति, समृद्धि एवं विकास लाना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में भगवान विष्णु के नाम पर यज्ञ का आयोजन करना तथा इसको भगवान राम को समर्पित करना अपने आप में गौरव का विषय है। यह यज्ञ पूर्ण रूप से वेद विज्ञान पर आधारित है इसके संस्थापक महंत महेश योगी एक उच्च कोटि के संत एवं साधक थें। 50 के दशक में तत्कालीन जगतगुरू से दीक्षा लेकर इन्होंने पूरे हिमालय सहित उत्तर दक्षिण के राज्यों केरल, कन्याकुमारी आदि का भ्रमण किया। भ्रमण करने के पश्चात हमारे वैदिक कालीन महता को विश्व में विशेषकर यूरोपियन, अफ्रीकन, अमेरिकन देशों में जाकर प्रचार प्रसार किया तथा विश्व में भारती संस्कृति एवं वेद की महत्ता को उजागर किया। महर्षि योगी जी के विदेशों में लाखों अनुयायी है। हमें भी इनसे मिलने का 1996 में मौका मिला था। इनको मैं उच्च कोटि का संत एवं विचारक के रूप में नमन करता हूं। इनके द्वारा स्थापित किये गये महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान अनेको कार्य कर रही है तथा इससे लाखों में वेद पाठी, विद्वान तैयार हो रहे है।

ओमिक्रॉन का असरः भारत ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानो का फैसला टाला

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट का असर भारत में पूर्व निर्धारित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर पड़ा है। पहले सरकार की तरफ से बताया गया था कि एक फैसले में तय किया गया है कि 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा। लेकिन अब इस फैसले को टाल दिया गया है। यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो पाएंगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफसे कहा गया है कि वो अपने पूर्व के फैसले की समीक्षा करेगा।

दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत और ब्रिटेन-बेल्जियम समेत कई देशों में यह वायरस पहुंच जाने के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। डीजीसीए ने कहा कि वह कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के उभार को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। डीजीसीए ने कहा कि वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख पर अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करेगा उसने 15 दिसंबर से विदेशी उड़ानों को पूरी तरह फिर शुरू करने के फैसले की समीक्षा करने का फैसला किया है।इससे पहले गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याम मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद भारत सरकार ने 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल उड़ाने शुरू करने का फैसला लिया था। पिछले साल कोरोना के चलते 23 मार्च को देश में नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद समय-समय पर कई देशों के साथ सीमित हवाई सेवा शुरू की गई थी।

पीएम मोदी की बैठक में हुई समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को ओमिक्रॉन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। इसमें 15 दिसंबर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। पीएम ने विदेश से आने वाले लोगों की सख्त निगरानी करने की बात भी कही थी। इसी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन वैरिएंट ने तांडव मचा दिया है। कई देशों में इस खतरनाक वैरिएंट को लेकर गाइडलाइंस बना दी गई हैं, वहीं कई जगह इसे लेकर ऐ?हतियात बरती जा रही है। वैरिएंट को ह्यूाह ने पहले ही 'वैरिएंट ऑफ कंसर्न', यानि चिंताजनक घोषित किया है। इससे पहले कनिष्ठ उड्डयन मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह ने सोमवार को कहा था कि अंतरराष्ट्रीय निर्धारित उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए जनता का जबरदस्त दबाव है। उन्होंने कहा था कि 'हम पर अंतरराष्ट्रीय निर्धारित उड़ानें शुरू करने के लिए जनता का जबरदस्त दबाव है। हम सभी प्रोटोकॉल और सावधानी बरत रहे हैं। बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति, विशेष रूप से पर्यटकों की हवाई अड्डे पर जांच और परीक्षण किया जा रहा है।

देश में फिर बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण

» 24 घंटे में 8,954 नए मामले, 267 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में एक दिन में करीब दो हजार कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 267 लोगों की जान चली गई है। वहीं 10,207 नए मरीज स्वस्थ्य होकर अस्पतालों से घर लौट चुके हैं। अब देश में सक्रीय मरीजों की संख्या तेजी के साथ घटकर एक लाख से नीचे आ गई है, जो बेहद राहत की बात है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। देशभर में उपचाराधीन मरीजों में कमी आ रही है और फिलहाल देश में सक्रीय मरीजों की संख्या 99,093रह गई हैं, जो कुल संक्रमण का 0.29 प्रतिशत शामिल है और यह आंकड़ा मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। जबकि देश में अब तक 3,45,96,776 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 4,69,247 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24घंटे में 1,520 सक्रिय मामलों में कमी आई है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और अब तक 3,40,81,183 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जिनकी रिकवरी दर 98.36 प्रतिशत हो गई है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है।

आजादी के 75 वर्ष बाद अब अबूझमाड़ में मिली इंटरनेट की आजादी

» अनसर्वेड अबूझमाड़ ब्लाक मुख्यालय ओरछा में शुरू हुई वीडियो कॉलिंग की सुविधा

नारायणपुर (आरएनएस)। आजादी के करीब 75 साल बाद अबूझमाड़ के लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिली है। देश-दुनिया की आधुनिकता से कोसों दूर माड़ के बासिंदे अब दुनिया को बुझने लगे हैं। आजाद भारत के अनसर्वेड अबूझमाड़ ब्लाक मुख्यालय में वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। कई दशकों बाद जिला मुख्यालय से 65 किमी दूर ओरछा तक ऑप्टिकल फाइबर के तार पहुंच जाने से माड़ की तस्वीर बदल रही है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में दिक्कतें नहीं हो रही है। इंटरनेट की सुविधाएं मिलने से अबूझमाड़ियों में भारी उत्साह दिख रहा है।

ओरछा की कमली, निलदई, सावित्री समेत कई महिलाएं और युवतियां अब इंटरनेट मीडिया से जुड़कर संवाद कर रही है। नक्सल हिंसा से ग्रसित अबूझमाड़ में इंटरनेट की सुविधा बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई है। अहम बात यह है कि पब्लिक डाटा ऑफिस सर्विस (पीडीओ) की शुरुआत छत्तीसगढ़ में बीएसएनल के द्वारा अबूझमाड़ से की गई है जिसकी सुविधा बहुत ही कम दर में देश की विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों को मिल रही है।

जवानों को मिली तनाव से मुक्ति- नक्सल मोर्चे पर तैनात फोर्स के जवान भी अब परिजनों से वीडियो कॉलिंग कर बात कर रहे हैं। जिससे परिजनों के साथ जवानों को बड़ी राहत मिल रही है। परिवार से दूर रहने का मलाल अब जवानों में नहीं दिख रहा है, जिससे जवान तनावमुक्त हो रहे है। मेट्रो सिटी की तर्ज पर इंटरनेट की सुविधा अबूझमाड़ के लोगों को मिल रही है।

सरकारी कामकाज में आई तेजी- आजादी के सात दशक बाद ओरछा ब्लाक मुख्यालय में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने से सरकारी योजनाओं की ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। वही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में भी काफी मदद मिल रही है। सरकारी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने अब अबूझमाड़ के लोगों को जिला मुख्यालय का सफर तय नहीं करना पड़ रहा है, जिससे समय और रुपये की बचत हो रही है।

जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा माड़ के लोगों को- ओरछा ब्लॉक मुख्यालय में संचालित विभिन्न विभागों के दफ्तरों को जिला मुख्यालय शिफ्ट कर दिया गया था जिसे अब वापस ओरछा लौटाया जा रहा है। अबूझमाड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कमली लेकामी कहती है कि इंटरनेट की वजह से ब्लाक के सभी कार्य नारायणपुर में होते थे अधिकारी भी बहाना बनाकर ओरछा से गायब रहते थे अब अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय में रहना पड़ेगा,जिससे लोगों के रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। सप्ताह में एक दिन आने वाले अधिकारी ज्यादा समय ओरछा में बिताएंगे।

बड़े शहरों में मिलने वाली इंटरनेट स्पीड- बीएसएनएल के एसडीओ ओमप्रकाश कश्यप ने बताया कि पहली बार ओरछा के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिल रही है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लाक मुख्यालय से सबसे पहले (पीडीओ) पब्लिक डाटा ऑफिस सर्विस शुरू की गई है। ओरछा में 50 कनेक्शन लग चुके है। लोगों में भारी उत्साह दिख रहा है। उन्होंने बताया कि 69 रुपये में 30 जीबी डाटा 30 दिनों के लिए मिल रहा है। बड़े शहर में मिलने वाली स्पीड ओरछा के लोगों को मिल रही है।